

संपादकीय



किसान ही हैं असंतोष की जड़ें

कृषि निर्भर परिवारों का आम उपभोग खर्च औसत ग्रमीण उपभोग खर्च से नीचे चला गया है। 2022-23 की इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में औसत घरेलू उपभोग खर्च 3,773 रुपये रहा। लेकिन कृषि निर्भर परिवारों का औसत खर्च 3,702 रुपये ही था। देश के किसान फिर आंदोलन की राह पर हैं। उनकी प्रमुख मांग है फसलों पर स्वामीनाथन फॉर्मले के मुताबिक एमएसपी की कानूनी गारंटी और संर्णी त्रश माफी। इन मांगों को पूरा करने के लिए कृषक समाज में जान बाजा पर लगा दिन की भावना पैदा हुई है। इसकी वजह समझनी हो, तो ताजा जारी घरेलू उपभोग खर्च सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर गौर करना उपयोगी होगा। इस रिपोर्ट से सामने आया है कि कृषि निर्भर परिवारों का आम उपभोग खर्च औसत ग्रमीण उपभोग खर्च से नीचे चला गया है। 2022-23 की इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में औसत घरेलू उपभोग खर्च 3,773 रुपये रहा। लेकिन कृषि निर्भर परिवारों का औसत खर्च 3,702 रुपये ही था। इसके पहले हुए हर घरेलू उपभोग खर्च सर्वे में कृषि आधारित परिवारों का औसत व्यय अन्य ग्रामीण परिवारों से अधिक रहा था। कृषि आधारित परिवारों में वे दिहाड़ी मजदूर और अन्य खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं, जिनकी आमदानी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इस नई सूरत की वजह क्या है, यह जानाना महत्वपूर्ण होगा। फिल्महाल चूंकि इस संबंध में ठोस सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। संभव है कि इसका एक कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दूसरे कारोबारों का बढ़ना हो। मसलन, पशुपालन या बागवानी जैसे धंधों में खेती से ज्यादा मुनाफा हो रहा हो। या फिर यह वजह हो सकती है कि कारोना महामारी के दौरान शहरों से गांव लैटे मजदूरों में से अनेक वहाँ रह गए हैं, जिससे श्रमिकों की अधिकता के कारण उनकी मजदूरी घट गई हो। लेकिन कुल मिलाकर यह तस्वीर तो उभरती ही है कि खेती लगातार गैर-लाभकारी होती जा रही है। इसका बड़ा कारण लागत में लगातार बढ़ोतारी और फसल की कीमत में भारी उत्तर-चढ़ाव रहे हैं। इस पर भी जस्तर गौर किया जाना चाहिए कि कृषि में सार्वजनिक पूंजीगत निवेश स्थिर बना हुआ है, जबकि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का अनिश्चय बढ़ गया है। इन कारणों से खेती अधिक जोखिम भारी पेशा बन गई है। ऐसे में किसानों और कृषि निर्भर अन्य तबकों में असंतोष पैदा होना एक स्वाभाविक घटना मानी जाएगी।

क्या लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन भाजपा के लिये चुनौती बन पायेगा?

अधिरो एवं निराशा के गत में जा चुके एवं लाभगम बिखर चुके इडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरों ने जहां उसमें नये उत्साह का संचार किया है वहां भारतीय जनता पार्टी के लिये चिन्ना के कारण उपत्र किये हैं। पहले उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में समाजवादी पार्टी और आम आदामी पार्टी से सीट बंटवारे पर बनी सहमति ने टूट की कगार पर पहुंचे इडिया गठबंधन में वर्ष 2024 के आम चुनावों को लेकर संभावनाभरी तस्वीर को प्रस्तुत किया है। अब ये चुनाव दिलचस्प होने के साथ कुछ सीटों पर काटे की टक्कर बाले होंगे। इन नये बन रहे चुनावी समाजकरणों के बावजूद भाजपा के लिये अभी कोई बड़ा संकट नहीं दिख रहा है। भले ही इडिया गठबंधन डींगे हांके कि वह भाजपा एवं उसके गठबंधन के लिए कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति आ गयी है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का जब गठबंधन बना तभी यह आशंका की गयी कि यह कितनी दूर चल पायेगा, टिक पायेगा भी या नहीं? कुछ हालात तो ऐसे भी बने कि इसके तार-तार होने की संभावनाएं बलवती हुईं। भले ही अब कुछ सीटों पर दलों के बीच सहमति बनी हो लेकिन अभी कई महीने रूप से झूँझू नाम घोषित अटकलों द सत्ता तक टूटन व गठबंधन में अकल्पना उठती है। र ही प्रश्नचिह्न होगी, ऐसा में टकराव मन-मुटाव लेकिन अ दिया गया होते। अवधार दोस्त को रूप में देन नफा-नुकसान बिखर रहे विखरी है गठबंधन व लगे। पहले दिसंबर के प्रदर्शन क बातचीत

नकल जाने के बाद भी विधिवत या गठबंधन के संयोजक का नहीं हो पाना अनेक सन्देहों एवं कारण बना हुआ है।
हुंचने के लिए जिस प्रकार दल-बंधन हो रहे हैं इससे सबके मन मरीय सम्भावनाओं की सिहरन और और राशीयता के अस्तित्व पर लगने लगा है। कुछ अनहोनी बल महसूस कर रहे हैं। प्रजातंत्र होता है। विचार फर्क भी होता है। भी होता है पर मर्यादापूर्वक। इस आधार को ताक पर रख। राजनीति में दुश्मन स्थाई नहीं रवादित दुश्मन को दोस्त और दूश्मन बना देती है। यह भी बड़े ने को मिल रहा है। राजनीति न का खेल बन रहा है, मूल्य हैं। चारों ओर सत्ता की भूख पिछले कुछ समय से ईडिया एक के बाद एक कई झटके तो कांग्रेस ने ही पिछले साल विधानसभा चुनावों में अच्छे उम्मीद में गठबंधन से जुड़ी तो ठंडे बरसे में डाले रखा। बातचीत शुरू भी हुई तो नेताओं पहले जैसा जोश दिखा और राजनीतिक जिजीविषा महसूस गठबंधन के प्रस्ताव पर सबसे बढ़ काम करने वाले नीतीश कुमार ही गए। यूपी में रालोद के जयंत ईडिया गठबंधन का हाथ थामते एनडीए में शामिल हो गए। ईडिया गठबंधन एवं कांग्रेस ने झटके झेले। छोटे-बड़े नेताओं कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला भी हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उच्चावहन का नाम खास तौर पर रहा। इसे चाहे इन नेताओं का व्यावसरावाद कहें या भाजपा और नेतृत्व की सक्रियता एवं राजनीति इतना तय है कि इन नेताओं को भविष्य खास अच्छा नहीं दिखा आदमी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी अपनी साख बचाने एवं सत्ता के रहने के लिये सीटों के बंटवारे बहुए हैं, उसमें कांग्रेस का बुटने उसकी टूटी सांसों को बजाए होना चाहिए। कांग्रेस दलों के बीच सहमति के स्वर

कया और अपनी स्पष्ट बहुमत बनाई। आम आदमी पार्टी रिक्रूटमेंट के चलते ही गुजरात में ने अब तक का सबसे निराशाजनक क्रिया। आम आदमी पार्टी ने गोवा स को काफी नुकसान पहुँचाया था। वहाँ में भी अपने संगठन का आवास। ताज कांग्रेस एवं आम आदमी की सहमति से कांग्रेस को न होना है। केजरीवाल की बजाए बनर्जी ने अलग छाप छोड़ी बगाल में कांग्रेस के लिए उन दो लोकसभा सीटों को ही छोड़त कह कर कांग्रेस के अधिक संसदीय वा करने के कारण स्वतंत्र चुनाव की घोषणा कर गठबंधन की क्रिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल बल्कि त्रिपुरा, असम और गोवा प्रांत चुनाव लड़ने की बात कह से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में ही हाथ लगी।

गठबंधन के नये बन रहे सकारात्मकों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतिक सेहत पर कोई असर नहीं। उनकी राजनीतिक परिपक्षता

परिचायक है। 2024 के चुनावों में भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य तय करने के मोदी के लक्ष्य के सामने अभी भी कोई बड़ी चुनौती दिखा नहीं रही है। इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाजपा एवं मोदी अपनी सीटों कहाँ से बढ़ा सकेंगे, इसके लिये भाजपा दोतरफा रणनीति पर काम कर रही है। पहली है, दक्षिणी राज्यों में पैठ बनाना। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि भाजपा पहले ही उत्तर-पश्चिम के कई राज्यों में चरम पर पहुंच चुकी है। दूसरी रणनीति है पुराने सहयोगियों को एनडीए में वापस लाने और नए सहयोगियों को जोड़ने की, जिसमें वह अब तक काफी हद तक सफल भी रही है। जदयू एनडीए के साथ फिर से आ गई है, गलोदाम भी एनडीए में लौट आई है, पंजाब में अकाली दल को वापस लाने के प्रयासों जारी हैं और टेदेओ के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। कछु और पार्टियां एनडीए में शामिल हो सकती हैं। लेकिन एनडीए के विस्तार भर से भाजपा को 2024 में 370 सीटें नहीं मिलने वालीं। अभी उसे काफी जोड़-तोड़ करने होंगे।

-ललित गर्ग-

ਤੁਮ ਅਰ ਤੁਮ ਰੋ ਟਣਟੇ



सोने के भाव और डिजाईन खराब होने के भय से उहें बॉक्स सहित छुपाया जाना संभव नहीं है। इन गहनों के चोरी होन का भय हमेशा मन को चिंतित किये रहता है, कई बार गहनों पर झुँझाल आती है और लगता है कि *यह टूम कम और टण्टो ज्यादा है।* हमारी इसी चिंता को बाजारवाद ने गहराई से समझते हिसाब से तय है। छोटे साईज के लॉकर का विभिन्न बैंकों में किराया 2500 से 5000 रुपये व बड़े साईज का सालाना किराया 5000 से 10000 रुपये तक है। जो अनावश्यक गहनों को रखने का अनावश्यक सालाना खर्च जीवनपर्यंत आपको बहन करना पड़ता है। अनावश्यक सोना खरीद

रक रखने से बह उपयोग में नहीं आता और उसका वजन भी बढ़ता नहीं है। अगर यही पैसा किसी कार्य में लगायें तो उससे परिवार को आर्थिक संबल और बच्चों को रोजगार मिलेगा।

आज परिवारों में जिस तरह शिक्षा बढ़ती है उसके अनुपात में ऐसी फिजूलखर्ची ज्यादा हुई है जिसका मुख्य कार्य केवल दिखावा है। आज सोने पर हो रहे अनावश्यक व्यय को रोकने की जरूरत आर्थिक रूप से कमज़ोर या मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा है। जिसके पास अथाह धन संपदा है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्यम वर्ग अपनी रोजना की मजदूरी में से पाई-पाई जोड़कर इकट्ठी करता है और बिना सोचे समझे एक दिन महंगे गहने खरीद कर उन्हें अलमारी में छुपाकर रखने को मजबूर होता है। ये गहने साल में दो-चार बार से ज्यादा नहीं पहने जाते हैं। यहां सोचने और विचारे वाली बात यह है कि हमारे इस कार्य से फायदा किसको हुआ, अगर विक्रेता (जैवलर्स) को हुआ तो क्या हमने पाई-पाई विक्रेता को आर्थिक संबल देने के लिए जोड़ी है। इस बात को कुछ लोग नकारते हुए सोना खरीदने की पैरवी जरूर करेंगे और कठिन समय में काम आने का हवाला जरूर देंगे। अगर

आप यह सोच कर सोना खरीद रहे हैं कि कठिन समय में काम आयेगा तो फिर आप गहने की जगह सोने का बिस्कूट या सोने गी डवी खरीदें ताकि आप पर मैकिंगचार्ज का भारा नहीं पड़ेगा। आज प्रत्येक दस ग्राम यानि एक तोला के भाव का 8 से 10 प्रतिशत मैकिंगचार्ज लगता है। जो प्रत्येक दस ग्राम पर 5000 से 8000 रुपये होता है, यह राशि खरीदार के कभी काम नहीं आती है। अगर आपको ये गहने कठिन समय में बेचने पड़े तो मैकिंगचार्ज का पैसा वापिस नहीं मिलेगा।

आज कर्मचारी वर्ग के परिवारों को गहनों के आर्थिक बोझ से बचाने की शक्ति जरूरत है और यह जिम्मेदारी हमारी बहिन, बेटियों को आगे आकर लेनी चाहिए ताकि अपने घर को अनावश्यक आर्थिक भार से बचाया जा सके। आज हमें गहनों के खर्च में कटौती करके शिक्षा के खर्च को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा का मदिर ही एक ऐसा स्थान है जहां पर खर्च किया हुआ धन बच्चे सूद सहित वापिस ला सकते हैं। इसलिए हमें टूप्य (गहनों) पर अनावश्यक धन व्यय करने से हमें बचना चाहिए।



डम-डम डमरु
शिव-शिव शब्द पिरोकर भोले,
माला एक बनाऊंगा,
क्या पत्रा क्या हीरा-मोती,
मणियों की थाल सजाऊंगा।

डम-डम डमरु
भोले शब्द थासों का साथी,
मन की बीन बजाऊंगा,
सिर पर हाँथ धरेंगे भोले,
भोले का हो जाऊंगा।

डम-डम डमरु ..



कातिंकेय कुमार
त्रिपाठी राम
गांधीनगर,
इंदौर, मध्यप्रदेश

समाचार पत्र में छपे
समाचार
एवं लेखों पर सम्पादक
की सहमति आवश्यक
नहीं है। हमारा ध्येय
तथ्यों के आधार पर
सटिक खबरें प्रकाशित
करना है न कि किसी
की भावनाओं को ठेस
पहुंचाना। सभी विवादों
का निपटारा अम्बिकापुर
न्यायालय
के अधीन होगा।

पाकिस्तान चुनाव में धांधली के मिले और सबूत, नेताओं के ऑडियो वायरल, बोले-हमारा जनादेश फर्जी

इस्लामाबाद, 28 फरवरी 2024।

पाकिस्तान में बीते दिनों ही आम चुनाव में इस्मान खान की पार्टी पीटीआई धांधली के गभीर अरोप लगा रहा है। बीते दिनों पाकिस्तान के एक पूर्व अधिकारी ने भी पीटीआई के दावों को सही ठहराते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अब एक बार फिर ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे पाकिस्तान के चुनाव में धांधली के दावों की पुष्टि होती है। दरअसल पाकिस्तान के दो नेताओं की ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें दाव किया जा रहा है कि पाकिस्तान के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और जनादेश की चोरी हुई।



एमव्यूएम नेता की ऑडियो लीक

पाकिस्तानी की राजनीतिक पार्टी मुत्तिहा की मीमेंट-पाकिस्तान (एमव्यूएम-पी) के नेता और सिंध गवर्नर कामरान तेसोरी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में तेसोरी कहते सुनाई दे रहे हैं कि वे कहते हैं कि हमारा जनादेश पूरी तरह से

फर्जी है। दरअसल तेसोरी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। वायरल ऑडियो में तेसोरी कहते हैं कि आज (8 फरवरी) हमें बोत नहीं मिले। अगर एमव्यूएम-पी ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सकार में शामिल होने का फैसला किया तो पार्टी के हालात बहुत दुर्घाट होंगे। हमें एक मंत्री पद मिल रहा है और गवर्नर पद भी लेने की बात कही जा रही है और गवर्नर पद भी लेने की बात कही जा रही है कि उनकी पार्टी के विरोधी दाव कर रहे हैं कि उनका जनादेश

पीटीआई ने एमव्यूएम-पी की जीत को बताया फर्जी

एमव्यूएम-पी के ही वरिष्ठ नेता मुस्तफा कमल का भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के

विश्वास खो चुके हैं।

फर्जी है। पीटीआई भी ऐसा ही दाव कर रही है। एमव्यूएम-पी को नेशनल असेंबली में 11 संटे मिली हैं। पीटीआई का गठबंधन को एमव्यूएम-पी के उम्मीदवारों को चुनाव में तीसरा स्थान भी नहीं मिला था। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों को 92 नेशनल असेंबली सीटों और पंजाब असेंबली में 100 सीटों पर जीत मिली है। वहीं नवाज शरीफ का पार्टी पीएमएल-एन को नेशनल असेंबली में 75 और पीटीआई को 54 सीटें मिली हैं। पीटीआई का दाव है कि अगर चुनाव में धांधली न हुई होती तो उन्हें नेशनल असेंबली में 180 और प्रांतीय असेंबली में 220 सीटें मिलतीं।

पाकिस्तान में पीएमएल-एन, पीटीआई, एमव्यूएम-पी समेत कई निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ मिलकर गठबंधन सकार बनाने का एलान किया है। शहबाज शरीफ नई सरकार में प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। वहीं एसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। हालांकि अभी तक शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का एलान नहीं किया गया है। गठबंधन की सहभागी पीटीआई खुद एमव्यूएम-पी की जीत पर सहायता देंगे।

पाकिस्तान में पीएमएल-एन, पीटीआई,

लंदन की कोर्ट से प्रिंस हैरी को झटका, सुरक्षा को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा होगे

लंदन, 28 फरवरी 2024।

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को लंदन हाईकोर्ट से झटका लगा है। ब्रिटेन में अपनी सुरक्षा को लेकर उहोने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अदालत का रुख किया था। मालूम होने के सुनवाई के दौरान न्यायाली सरपाई लेने वाले ने कहा कि पुलिस सुरक्षा हटाने का फैसला गैरकैनी था।



अपने देश में हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ अमेरिका में स्थानांतरित हो गए थे। उहोने तर्क दिया था कि उनकी सुरक्षा स्टर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उनके बच्चों ने अदालत को बताया कि जब वह

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

उहोने देश में हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ अमेरिका में स्थानांतरित हो गए थे। उहोने तर्क दिया था कि उनकी सुरक्षा स्टर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उनके बच्चों ने अदालत को बताया कि जब वह

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

उहोने देश में हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ अमेरिका में स्थानांतरित हो गए थे। उहोने तर्क दिया था कि उनकी सुरक्षा स्टर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उनके बच्चों ने अदालत को बताया कि जब वह

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

उहोने देश में हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ अमेरिका में स्थानांतरित हो गए थे। उहोने तर्क दिया था कि उनकी सुरक्षा स्टर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उनके बच्चों ने अदालत को बताया कि जब वह

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

उहोने देश में हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ अमेरिका में स्थानांतरित हो गए थे। उहोने तर्क दिया था कि उनकी सुरक्षा स्टर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उनके बच्चों ने अदालत को बताया कि जब वह

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

उहोने देश में हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ अमेरिका में स्थानांतरित हो गए थे। उहोने तर्क दिया था कि उनकी सुरक्षा स्टर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उनके बच्चों ने अदालत को बताया कि जब वह

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

उहोने देश में हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ अमेरिका में स्थानांतरित हो गए थे। उहोने तर्क दिया था कि उनकी सुरक्षा स्टर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उनके बच्चों ने अदालत को बताया कि जब वह

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

उहोने देश में हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ अमेरिका में स्थानांतरित हो गए थे। उहोने तर्क दिया था कि उनकी सुरक्षा स्टर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उनके बच्चों ने अदालत को बताया कि जब वह

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

उहोने देश में हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ अमेरिका में स्थानांतरित हो गए थे। उहोने तर्क दिया था कि उनकी सुरक्षा स्टर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उनके बच्चों ने अदालत को बताया कि जब वह

समिति (आरएवीईसी) के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। पिछले साल, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की बायाके के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए निजी भुगतान करने का मुकदमा भी हार गए थे।

उहोने देश में हैं तो उ

खेलमंत्री ने विधानसभा में पूर्व सरकार के लापरवाही का मामला उठाया

» पांच साल में भूपैश सरकार में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को न तो समान मिला न ही नौकरी
» खेल मंत्री टंकराम के जवाब पर अद्यक्ष भी चौके

रायपुर, 28 फरवरी 2024 (ए)। विधानसभा में आज प्रदेश के खिलाड़ियों को लेकर चिंता की गई। भूपैश विधाक लता उत्कृष्ट की अनुपस्थिति पर सरन में उनकी ओर से पार्टी के विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्नकाल में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन और शासकीय सेवा में नियुक्ति को लेकर मामला उठाया। इस पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि भूपैश विधायक सरकार आने के बाद पिछले सालों में न तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची प्रकाशित हुई, न कोई अलंकरण समारोह हुआ और न ही उन्हें नौकरी दी गई।

अद्यक्ष ने की ये टिप्पणी...

इस मुद्रे विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा, 5 सालों में इस दिवस में कोई कसम नहीं उठाया गया, ये अद्भुत है। मंत्री टंकराम वर्मा ने आगे कहा, विष्णुव नायर सरकार खिलाड़ियों को बेहतरी के लिए तमाम कदम उठाए हैं।



जल्द ही होगा अलंकरण समारोह
मंत्री ने बताया कि जल्द ही अलंकरण समारोह होने वाला है। आगे भी अलंकरण और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लेकर चयन करने की प्रक्रिया होगी।

पैसासूय में नौकरी के लिए कहें
खिलाड़ियों को लेकर हो रही चयनी के द्वारा इस समारोह को लेकर हो रही चयनी को नौकरी देने के लिए दिल्ली जायें।

खिलाड़ियों को नौकरी के लिए अप्रक्षण है। इस पर सुशांत शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में सचिलित नौकरी देने के लिए दिल्ली जायें।

एमएलए धरमजीत ने कहा पता नहीं कहां-कहां

भाजा विधायक धरमजीत सिंह ने कहा, पिछली सरकार में वास्तविक खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलता था, पता नहीं कहां-कहां से लाए थे। उन्होंने इस पर चिंता जाते हुए कहा कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने के प्रावधान को लेकर पूछा कि अब प्रदेश में खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी या नहीं?

सर्वजनिक प्रतिशतों को भी खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए दिल्ली जायें।

मंत्री केदार कश्यप ने बताया

वन्यजीवों के मौत का कारण

वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जंगल सफारी के वन्यजीवों का आवश्यक दबाएं दी जा रही है।

टीकाकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी वन्यजीव की उम्र ज्यादा हो गई थी, तो कुछ लोगों की आपसी झगड़ में मौत हुई। वन्य प्राणियों के सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था, है।

विधायक शेषराज हरबंस ने पूछा कि इस मामले में किसी अधिकारी और डॉक्टर के लापरवाही सामने आई है। वन मंत्री ने बताया कि जंगल सफारी में सेंट्रल जू. अंथरिटी से इसकी जांच कराने के कारण दम तोड़ दिया। 2 नील गायों की मौत की वजह अंतरिक चोट बैठाई गई। एक चीविंग व एक चीताल की मौत निर्माणिया के कारण हुई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महत के एक प्रकरण के लिखित तरफ में दी है। वन मंत्री ने बताया कि जंगल सफारी में 2 वन्यप्राणी डॉक्टर रखे गए हैं। मंत्री ने यह भी बताया है कि वन्य जीवों के संबंध में जू. कॉर्पस पहली सूचना वन्यप्राणी डॉक्टरों को देते हैं।

चिकित्सा का कंपांडर भी है।

2 डॉक्टरों को

शोकांज नोटिस जारी

विधायक शेषराज हरबंस ने पूछा कि

वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जंगल सफारी के वन्यजीवों का आवश्यक दबाएं दी जा रही है।

टीकाकरण का प्रयास भी किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि किसी वन्यजीव की उम्र ज्यादा हो गई थी, तो कुछ लोगों की आपसी झगड़ में मौत हुई। वन्य प्राणियों के सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था, है।

विधायक शेषराज हरबंस ने पूछा कि इस मामले में किसी अधिकारी और डॉक्टर के लापरवाही सामने आई है।

वन मंत्री ने बताया कि जंगल सफारी में सेंट्रल जू. अंथरिटी से इसकी जांच कराने के कारण दम तोड़ दिया। 2 नील गायों की मौत की वजह अंतरिक चोट बैठाई गई। एक चीविंग व एक चीताल की मौत निर्माणिया के कारण हुई है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महत के एक प्रकरण के लिखित तरफ में दी है। वन मंत्री ने बताया कि जंगल सफारी में 2 वन्यप्राणी डॉक्टर रखे गए हैं। मंत्री ने यह भी बताया है कि वन्य जीवों के संबंध में जू. कॉर्पस पहली सूचना वन्यप्राणी डॉक्टरों को देते हैं।

सकती है नेता प्रतिपक्ष की अपार्टमेंट के बीच राजसा मूनत ने ध्यानाकरण पढ़ा।

नारीवाली निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है। राजश्री समिति का समुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक करा लिया गया है। राजश्री समिति ने बताया कि जंगल सफारी का एलान किया। डॉ. राकेश वर्मा और कंपांडर सोनल मिश्र के खिलाफ को शोकांज नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया है।

कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा जांच कराने का एलान किया।

सकती है नेता प्रतिपक्ष की अपार्टमेंट के बीच राजसा मूनत ने ध्यानाकरण पढ़ा।

नारीवाली निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है। राजश्री समिति का समुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक करा लिया गया है। राजश्री समिति ने बताया कि जंगल सफारी का एलान किया। डॉ. राकेश वर्मा और कंपांडर सोनल मिश्र के खिलाफ को शोकांज नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया है।

कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा जांच कराने का एलान किया।

सकती है नेता प्रतिपक्ष की अपार्टमेंट के बीच राजसा मूनत ने ध्यानाकरण पढ़ा।

नारीवाली निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है। राजश्री समिति का समुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक करा लिया गया है। राजश्री समिति ने बताया कि जंगल सफारी का एलान किया। डॉ. राकेश वर्मा और कंपांडर सोनल मिश्र के खिलाफ को शोकांज नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया है।

कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा जांच कराने का एलान किया।

सकती है नेता प्रतिपक्ष की अपार्टमेंट के बीच राजसा मूनत ने ध्यानाकरण पढ़ा।

नारीवाली निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है। राजश्री समिति का समुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक करा लिया गया है। राजश्री समिति ने बताया कि जंगल सफारी का एलान किया। डॉ. राकेश वर्मा और कंपांडर सोनल मिश्र के खिलाफ को शोकांज नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया है।

कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा जांच कराने का एलान किया।

सकती है नेता प्रतिपक्ष की अपार्टमेंट के बीच राजसा मूनत ने ध्यानाकरण पढ़ा।

नारीवाली निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है। राजश्री समिति का समुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक करा लिया गया है। राजश्री समिति ने बताया कि जंगल सफारी का एलान किया। डॉ. राकेश वर्मा और कंपांडर सोनल मिश्र के खिलाफ को शोकांज नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया है।

कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा जांच कराने का एलान किया।

सकती है नेता प्रतिपक्ष की अपार्टमेंट के बीच राजसा मूनत ने ध्यानाकरण पढ़ा।

नारीवाली निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है। राजश्री समिति का समुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक करा लिया गया है। राजश्री समिति ने बताया कि जंगल सफारी का एलान किया। डॉ. राकेश वर्मा और कंपांडर सोनल मिश्र के खिलाफ को शोकांज नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया है।

कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं क